www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए
DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 180 | जौनपुर शनिवार, 14 फरवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

पीएम मोदी ने असमवासियों को देंगे 5,450 करोड़ की सौगात

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को असम के दौरे पर जाएंगे। उनका यह दौरा पूर्वोत्तर भारत के विकास को नई रफ्तार देने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सुबह करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ईएलएफ) पर उतरेंगे। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला आपातकालीन लैंडिंग केंद्र है। यहां वे फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टरों का हवाई प्रदर्शन देखेंगे। भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय में तैयार किया गया यह ईएलएफ आपात स्थिति में सैन्य और नागरिक विमानों की लैंडिंग और टेक–ऑफ में सक्षम है। प्राकृतिक आपदा या रणनीतिक जरूरतों के समय यह राहत और बचाव कार्यों के लिए बेहद अहम साबित होगा। यह ढांचा 40 टन तक के फाइटर विमान और 74 टन अधिकतम टेक–ऑफ वजन वाले ट्रांसपोर्ट विमान संभाल सकता है। दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का दौरा करेंगे। करीब 3,030 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 6–लेन एक्स्ट्राडोज्ड प्री–स्ट्रेस्ड कंक्रीट (पीएससी) पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है। यह पूर्वोत्तर का पहला एक्स्ट्राडोज्ड पुल है और इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर सिर्फ 7 मिनट रह जाएगा। भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पुल में फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग के साथ बेस आइसोलेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मजबूती और दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए हाई–परफॉर्मेंस स्टे केबल लगाए गए हैं। साथ ही ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम (बीएचएमएस) भी जोड़ा गया है, जो रियल–टाइम निगरानी और संभावित क्षति का समय रहते पता लगाने में मदद करेगा। दोपहर 1रू30 बजे प्रधानमंत्री गुवाहाटी के लाचित घाट पर 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, डिजिटल ढांचे को मजबूत करना, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना है। कामरूप जिले के अमिंगांव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी उद्घाटन किया जाएगा। 8.5 मेगावॉट की स्वीकृत क्षमता और प्रति रैक औसतन 10 किलोवॉट क्षमता वाला यह अत्याधुनिक डेटा सेंटर विभिन्न सरकारी विभागों के मिशन–क्रिटिकल एप्लीकेशन होस्ट करेगा और अन्य राष्ट्रीय डेटा केंद्रों के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर के रूप में भी काम करेगा।

सत्ता के लिए बिन पानी मछली जैसी कांग्रेस : अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी बिन पानी मछली की तरह तड़प रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 60 साल तक देश की सत्ता में रही, आज उसकी स्थिति खराब हो चुकी है।भाजपा सांसद ने कहा कि नेता विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं करने दी और जब बजट शुरू हुआ, तो बजट पर कुछ नहीं बोले, बाकी सब कुछ बोले। जिस व्यक्ति को ट्रेड एंड कॉमर्स और फाइनेंस में अंतर नहीं पता, वो बाकी क्या करेगा? जिसको यह नहीं पता कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या बोले और बाकी पर क्या बोले, तो आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है। टेबल पर कूदकर हंगामा करते हैं, बेवजह के आरोप लगाते हैं, उनकी बातों में तथ्य होते नहीं हैं। स्पीकर का घेराव करते हैं। यह कैसी हालत है? कांग्रेस पार्टी यह करती है। 60 साल तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी, जो आज सत्ता से बाहर है, उसकी स्थिति यह है कि सत्ता के लिए ऐसे तड़प रही है जैसे पानी बिन मछली तड़पती है।उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 95 चुनाव हार चुकी है। अगले कुछ ही महीनों में इनका हार का शतक भी पूरा हो जाएगा। ये लोग इतने राष्ट्र विरोधी हो गए हैं कि लगता है इनके अंदर अंकल सैम की सिम और सोरोस का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। उधर से जो टाइप होता है, वही इधर से टेलिकास्ट होता है। भाजपा सांसद ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को मजबूत करते हुए इसे ऊपर उठाया है।

संक्षिप्त खबरें

देश को बदनाम करने का मौका नहीं चूकते राहुल गांधी : शाहनवाज हुसैन

कानपुर, (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लोकसभा में दिए बयान पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद के लिए बोझ बन गए हैं। वे मर्यादा तोड़ रहे हैं और विदेशी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। देश को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। कानपुर में भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी देश के पक्ष में नहीं बोलेंगे, उन्होंने कसम खाई है। भारत विरोधियों की पसंद वाली बातें वे बोलते हैं। पीएम पर हमले के लिए, महिला सांसदों को उकसाया। स्पीकर की बात नहीं मान रहे हैं।राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग संसद में कर रहे हैं, वह विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना का पूरा अधिकार है, लेकिन आरोपों की राजनीति और उत्तेजक शब्दों का इस्तेमाल करना स्वस्थ परंपरा नहीं है। देश को बेच दिया जैसे बयान न केवल राजनीतिक रूप से गैर–जिम्मेदाराना हैं, बल्कि इससे देश की संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न लगाने का प्रयास होता है। सरकार की नीतियों का विरोध करना अलग बात है, लेकिन देश की छवि को कमजोर करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रम पैदा करना उचित नहीं है। भारत की संसद बहस और विचार का मंच है, न कि सनसनी फैलाने का स्थान। पूर्व में कई विपक्षी नेताओं ने तीखा विरोध किया, परंतु उन्होंने कभी भी शब्दों की मर्यादा नहीं छोड़ी और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा।

बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी भारत के हित में : आनंद परांजपे

मुंबई, (एजेंसी)। बांग्लादेश के आम चुनाव को लेकर एनसीपी नेता आनंद परांजपे ने कहा कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी वापस आना भारत के नजरिए से भी जरूरी है। एनसीपी नेता आनंद परांजपे ने कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पड़ोसी देश में लोकतंत्र बहाल हो। आज बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार के लिए चुनाव हो रहे हैं, जो एक सकारात्मक कदम है। हालांकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि वहां अल्पसंख्यक हिंदू लगातार हमलों का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। फिर भी, बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी भारत के हित में भी है।अजित पवार की मौत पर रोहित पवार द्वारा शक जताए जाने पर एनसीपी नेता आनंद परांजपे ने कहा कि पहले दिन से ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने स्पष्ट रुख अपनाया है। 28 तारीख को हैंडल एयरो में सुबह 7:03 बजे व्हाट्सएप पर प्रेजेंटेशन दिखाया गया था कि सब कुछ साफ है–बारामती में विजिबिलिटी ठीक थी और सब कुछ सामान्य होना चाहिए था। उस समय से लेकर सुबह 8:44 बजे तक, जब प्लेन क्रैश हुआ।

हर क्षेत्र में निर्णय उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों को लेने चाहिए : मोहन भागवत

नागपु, (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गुरुवार को एक अलग और सशक्त वेटरिनरी काउंसिल के गठन की पैरवी की। उन्होंने कहा कि जानवरों और जनसुरक्षा से जुड़े फैसले वेटरिनरी डॉक्टरों और विषय–विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ही होने चाहिए। भागवत नागपुर में इंडियन सोसायटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ कैनाइन प्रैक्टिस (आईएसएसीपी) के 22वें वार्षिक अधिवेशन और श्रोल ऑफ कैनाइन इन वन हेल्थरू बिल्डिंग पार्टनरशिप्स एंड रिजॉल्विंग चौलेंजेजश विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इसका आयोजन आईएसएसीपी, महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी (एमएएफएसयू), नागपुर और नेशनल एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स एंड रिसर्च (एनएडब्ल्यूएआर) ने संयुक्त रूप से किया। अपने संबोधन की शुरुआत में भागवत ने कहा, ष्मैंने इसी कॉलेज में पढ़ाई की है। हालांकि मुझे वेटरिनरी क्षेत्र छोड़े 50 साल हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन आप लोगों जितना ज्ञान अब मेरे पास नहीं है। फिर भी पूर्व छात्र के रूप में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आभारी हूं।ष उन्होंने कहा कि भारत जैसे कृषि–आधारित देश को तब तक लाभ मिलता रहा, जब तक किसान खेती के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन भी करते रहे। मोहन भागवत ने वेटरिनरी पेशे के दायरे को सीमित मानने की सोच को गलत बताते हुए।

भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा : केशव प्रसाद मौर्य

नई दिल्ली, (एजेंसी)। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर देशभर में सियासी बहस तेज हो गई है। अलग–अलग दलों के नेताओं ने अपने–अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ष्कोई भी श्वंदे मातरमश का विरोध नहीं कर पाएगा। भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। जो इसका विरोध करेगा, उसके असली रंग सामने आ जाएंगे।ष दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसका विरोध करते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। आप वंदे मातरम पढ़ेंगे तो हम भी खड़े होंगे। लेकिन आप मुझसे मेरी इबादत का तरीका बदलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैं इसे नहीं बदलूंगा। मेरे संविधान ने मुझे इसकी अनुमति दी है।ष मुंबई के उपमहापौर संजय घाडी ने संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि केंद्र या राज्य सरकार कोई कानून बनाती है और उसे लागू करती है तो नागरिकों को उसका पालन करना चाहिए। लेकिन यह किसी धर्म के विरोध में नहीं होना चाहिए। हमें एक–दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। भाजपा सांसद मयंकभाई नायक ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार ने पूरा श्वंदे मातरमश गाने का फैसला किया तो कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा, ष्वंदे मातरम किसी देवी–देवता का नाम नहीं है, यह मातृभूमि का सम्मान है। एक सच्चे देशभक्त को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।ष उन्होंने नासिक पर्व की अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें अपने जन्मस्थान पर श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य मिला। शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने कहा कि वंदे मातरम हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रहित का विषय है। भारत में रहना है तो श्वंदे मातरमश गाना होगा। अगर नहीं आता तो सीखना चाहिए। राष्ट्रगान श्जन गण मनश है, लेकिन राष्ट्रीय गीत श्वंदे मातरमश विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने जमीयत उलेमा–ए–हिंद के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विरोध का कोई असर नहीं पड़ेगा।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डिजिटल क्रांति का हुआ अभूतपूर्व विस्तार : सिंधिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद भवन, नई दिल्ली। केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज संसद में प्रश्नों के उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में आए ऐतिहासिक बदलावों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारतनेट विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक तक सस्ती और तेज इंटरनेट सुविधा पहुँचाना है। केन्द्रीय मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि वर्ष 2014 में देश में 93 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता थे, जो आज बढ़कर 120 करोड़ हो चुके हैं और मोबाइल पेनिट्रेशन 75 प्रतिशत से बढ़कर 92 प्रतिशत तक पहुँच गया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी क्रांतिकारी बदलाव आया है। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 2014 के 25 करोड़ से बढ़कर आज 100 करोड़ से अधिक हो गई है, और पेनिट्रेशन 20 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 71.8 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। इसी तरह, ब्रॉडबैंड उपभोक्ता 6 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ से अधिक हो गए हैं, जबकि औसत ब्रॉडबैंड स्पीड लगभग 66 एमबीपीएस तक पहुँच चुकी है। सिंधिया ने इसे डिजिटल क्रांति बताते हुए कहा कि कनेक्टिविटी अब शहरी विशेषाधिकार नहीं रही, बल्कि ग्रामीण भारत तक पहुँचने वाला नागरिक अधिकार बन चुकी है। सिंधिया ने बताया कि ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की प्रमुख योजना भारतनेट के तहत देश की 2.56 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है। भारतनेट ᴵ और ᴵᴵ के अंतर्गत लगभग ध्42,000 करोड़ के निवेश से 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है। अमेंडेड भारतनेट प्रोग्राम, जिसकी कुल लागत लगभग 16.9 बिलियन डॉलर है, आज विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण कनेक्टिविटी पहल बन चुका है। इसका लक्ष्य शेष क्षेत्रों को जोड़कर अंतिम छोर तक निर्बाध इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करना है। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि नेटवर्क आर्किटेक्चर को लाइन टोपोलॉजी से रिंग टोपोलॉजी मॉडल में उन्नत किया जा रहा है। इस बदलाव से यदि किसी एक दिशा से कनेक्टिविटी बाधित होती है, तो दूसरी दिशा से सेवाएँ निर्बाध जारी रहेंगी, जिससे नेटवर्क की विश्वसनीयता और अपटाइम में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

जनगणना में स्पष्टता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोपरि : सीएम मोहन यादव

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगामी समय में होने वाली जनगणना को पिछली जनगणना से अलग बताते हुए कहा है कि इसमें स्पष्टता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोपरि रहनी चाहिए। सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में जनगणना – 2027 पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का शुभारंभ किया। सीएम मोहन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कार्यक्रम से जुड़ी फोटो शेयर करते हुए लिखा, ष्आज भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में जनगणना – 2027 पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ऐतिहासिक जनगणना होने जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश, देश के लिए आदर्श मॉडल बनकर उभरेगा और भारत सरकार की अपेक्षाओं एवं उद्देश्यों की सफल पूर्ति करेगा।ष उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डाटा प्रक्रिया है। इसके आधार पर सरकार की योजनाएं बनती हैं, संसाधनों का वितरण तय होता है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने की रणनीति तैयार होती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस बार की जनगणना भले ही आंठवीं है, लेकिन सबसे अलग है। कोविड के कठिन काल में स्वाभाविक रूप से जनगणना संभव नहीं थी, लेकिन अब हमें अधिक शुद्धता और पारदर्शिता के साथ यह दायित्व निभाना है। गणनाओं की शुद्धता और बारीकियों के लिए प्रशिक्षण हुआ है, अब प्रतिबद्धता और निष्पक्षता सबसे पहली शर्त है। सीएम मोहन यादव ने जनगणना के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि जनगणना के कई अर्थ निकाले जाएंगे, इसलिए स्पष्टता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोपरि रहनी चाहिए। 1931 के बाद सामाजिक स्तर की इस प्रकार की जनगणना पहली बार हो रही है, हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं।

सीएम धामी ने बद्रीनाथ तथा केदारनाथ धाम में हेलीपैड विस्तार एवं सुधारीकरण कार्य के लिए स्वीकृत की धनराशि

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में विकासखंड ज्योर्तिमठ के अंतर्गत बद्रीनाथ धाम में यूकाडा द्वारा संचालित स्थाई हेलीपैड के प्लेटफार्म विस्तार एवं एप्रोच रोड के सुधारीकरण संबंधित कार्यों के लिए 1.74 करोड़ रुपए और केदारनाथ धाम में जीएमवीएन के समीप स्थित हेलीपैड के सुरक्षात्मक कार्य के लिए 39.40 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।मुख्यमंत्री द्वारा नन्दा राजजात यात्रा–2026 हेतु विकासखण्ड थराली के अन्तर्गत शहीद भवानी दत्त इण्टर कॉलेज परिसर चौपड्ध्यों में पार्किंग एवं विश्राम गृह का निर्माण (क्षमता–08 चौपहिया वाहन) हेतु 71.67 लाख रुपए, विकासखण्ड देवाल के अन्तर्गत जनता इण्टर कॉलेज, सरकोट में 63 चौपहिया वाहन एवं 09 दुपहिया वाहन क्षमता हेतु पार्किंग तथा 02 कक्षों का विश्राम गृह एवं शौचालय के निर्माण हेतु 1.14 करोड़ रुपए, विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत नौटी में 37 चौपहिया वाहन एवं 48 दुपहिया वाहन क्षमता की सरफेस पार्किंग निर्माण हेतु 42.39 लाख रुपए, विकासखण्ड नारायण बगड़ के अन्तर्गत मगोती में 94 चौपहिया वाहन क्षमता की सरफेस पार्किंग निर्माण कार्य हेतु 79.56 लाख रुपए, विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कांसुवा में 43 चौपहिया वाहन क्षमता की सरफेस पार्किंग के निर्माण हेतु 64.23 लाख रुपए सहित विकासखण्ड थराली के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक, कुलसारी के पास थराली–ग्वालदम मोटर मार्ग के बायीं तरफ 89 चौपहिया वाहन क्षमता हेतु अस्थाई वाहन पार्किंग निर्माण हेतु 5.51 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

किसानों के हितों से किसी कीमत पर समझौता नहीं : राहुल गांधी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर संसद में उठे विवाद के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने आरोपों को दोहराते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के प्रस्ताव और सत्तापक्ष की ओर से हो रही आलोचनाओं के बावजूद राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि वे अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाए या उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका दावा है कि उन्होंने संसद में जो कहा, वह किसानों और देश के हितों से जुड़ी सच्चाई है।सरकार और भाजपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक वीडियो जारी कर अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि जो भी व्यापार समझौता किसानों की आजीविका को प्रभावित करता है और देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करता है, वह किसान–विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस डील के जरिए भारतीय कृषि बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोला जा रहा है, जिससे देश के छोटे और सीमांत किसानों पर गंभीर असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होने देगी।राहुल गांधी ने विशेष रूप से इस समझौते में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 'नॉन–टैरिफ बैरियर' हटाने के प्रावधान पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि ऐसे प्रावधान भारतीय बाजार को विदेशी कृषि उत्पादों के लिए अधिक सुलभ बना देंगे। उन्होंने दावा किया कि इससे कपास, सोयाबीन, ज्वार, फल और ड्राय फ्रूट्स जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले किसानों पर सीधा असर पड़ेगा। राहुल गांधी के मुताबिक, भारत के 99.5 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास पर्याप्त संसाधन, सब्सिडी या सुरक्षा तंत्र नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारतीय किसानों को सब्सिडी प्राप्त और बड़े पैमाने पर उत्पादित अमेरिकी कृषि उत्पादों से मुकाबला करना पड़ा, तो वे टिक नहीं पाएंगे ।

संपादकीय

प्रकाशन के इंतजार में नरावणे की किताब

सत्ता पक्ष के मुताबिक चूंकि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए उसमें वर्णित मामलों का उल्लेख सदन में नहीं हो सकता। मगर किताब का प्रकाशन किसने रोक रखा है? बेहतर होगा कि प्रकाशन की मंजूरी अविलंब दी जाए। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरावणे की किताब लगभग 21 महीनों से प्रकाशन के इंतजार में है, क्योंकि उसे केंद्र से हरी झंडी नहीं मिली है। अब उस किताब में वर्णित बातों को लेकर एक अंग्रेजी पत्रिका ने लंबी रिपोर्ट छापी है। उसमें शामिल एक प्रकरण का हवाला विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा में देना चाहते थे। मगर सत्ता पक्ष की आपत्तियों के बीच स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। बहरहाल, कांग्रेस ने उस पूरी रिपोर्ट को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाल कर उसे जनमत के बड़े हिस्से तक पहुंचा दिया है। इसके मुताबिक अगस्त 2020 में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण कैलाश रेंज की चोटी पर भारतीय फौज के नियंत्रण के बाद चीन ने हमला करने की तैयारी की थी। जब टैंकों समेत चीनी सेना की टुकड़ियां आगे बढ़ रही थीं, तब तत्कालीन सेनाध्यक्ष नरावणे ने बार-बार रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और विदेश मंत्री को फोन कर जवाबी कार्रवाई के लिए निर्देश मांगे। मगर इस पर घंटों तक टाल-मटोल की गई। आखिरकार प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद राजनाथ सिंह ने उन्हें निर्देश दिया- जो उचित लगे, वह करें। स्पष्टतरू ये प्रकरण वर्तमान सरकार की नेतृत्व क्षमता एवं संकल्प शक्ति को कठघरे में खड़ा करता है। सेना युद्ध संबंधी फौरी (टैक्टिल) फैसले ले सकती है, लेकिन ऑपरेशनल एवं रणनीतिक निर्णय लेने की स्थिति में सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व होता है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल नरावणे के सामने कई कठिन प्रश्न थे। कोरोना के कारण देश अस्त-व्यस्त था, जिससे मोर्चों पर सहज सप्लाई को लेकर आशंकाएं थीं। फिर युद्ध फैलता, तो विदेश नीति एवं कूटनीति संबंधी उसके परिणामों का आकलन सरकार ही कर सकती थी। मगर उस कठिन घड़ी में केंद्र ने जिम्मेदारी सेनाध्यक्ष पर टाल दी। सत्ता पक्ष का कहना है कि चूंकि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए उसमें वर्णित मामलों का उल्लेख सदन में नहीं हो सकता। मगर प्रश्न है कि किताब का प्रकाशन किसने रोक रखा है? सरकार के पास कुछ ढकने को नहीं है, तो बेहतर होगा कि वह तुरंत किताब प्रकाशन की मंजूरी दे, ताकि देश तत्कालीन सेनाध्यक्ष के अनुभव उनके ही शब्दों में जान सके।

संसदीय गतिरोध की राजनीति

अरविन्द

सदन में किताब की जानकारी पर चर्चा नहीं हो सकती जैसा तर्क भी लचर है पर ये छोटी बातें हैं बड़ी बात सदन न चलना और संसदीय कामकाज का पटरी से उतरना है। सदन की कमेटियों में काम नहीं हो रहा है। बिल को चुपचाप और झटपट लाकर बहुमत के जोर से पास कराया जाता है। मात्र दो संयुक्त संसदीय समितियां काम कर रही हैं, वक्फ बिल पर बनी समिति ने विपक्ष के एक भी सुझाव को नहीं माना और सबको खारिज किया। कहने को संसद का बजट सत्र चल रहा है लेकिन संसदीय कार्य और उसकी मंजूरी से चलने वाले जरूरी सरकारी कामकाज के हिसाब को देखा जाए तो एक बड़ा शून्य न भी दिखे लेकिन सरकार और विपक्ष ने पास नंबर भी हासिल किया हो ऐसा नहीं लगता। दूसरी ओर राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पेश होने जैसी न्यूनतम जरूरी कार्रवाइयों के अलावा जितनी राजनीति हावी रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, उसने संसदीय काम नहीं होने दिया है या जो काम हुए हैं उनकी मर्यादा को भी कम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने एक हास्यास्पद बहाना बनाकर प्रधानमंत्री को सदन में उपस्थित होकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने से बचने की इजाजत दे दी। ऐसा मुल्क के इतिहास में ही नहीं दुनिया के इतिहास में भी शायद ही कहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री विपक्षी की महिला सांसदों के संभावित हमले के अंदेशे से सदन में भाषण न दें। और फिर जब वे राज्य सभा में बोलें तो विपक्ष की महिला सांसदों का व्यवहार पूरा मर्यादित रहा। विपक्ष के नेता को बोलने से रोका गया हो लेकिन उसे तरह की श्गलतियांश करते हुए भाजपा के विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे को बोलने की इजाजत दे दी जाए।जब विपक्ष के नेता को सदन में बोलने से लगातार रोका जाए और हंगामे के नाम पर सदन न चले तो कई तरह के सवाल उठेंगे ही। और हैरानी की बात नहीं है कि सरकारी पक्ष ही नहीं मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सदन न चलने के साथ सार्वजनिक धन की बर्बादी का वही पुराना राग आलाप रहा है जो जमाना पहले कहा जाता था। इसी शासक दल या मीडिया ने आजकल सरकार की तरफ से होने वाले किसी भी शाहखर्ची पर, चुनाव में भारी धन की बर्बादी या नेताओंध्पैसे वालों द्वारा सामाजिक आयोजनों पर भारी खर्च पर कभी आपत्ति की होती तो उनकी विश्वसनीयता भी रही। यह सवाल उठाकर मीडिया भी सरकारी भोंपू लगती है पर असली सवाल सदन चलाने का है। और राहुल गांधी जिस बात पर आड़े हैं और और पूरे विपक्ष को एक बार और गोलबंद करने में सफल लगते हैं वह काफी हल्का है। यह सही है कि सदन में विपक्ष के नेता को बोलने की आजादी तो रहनी चाहिए और अगर अध्यक्ष और सरकारी पक्ष किसी भी कारण से उन्हें रोकता है तो गलत कर रहा है। लेकिन राहुल जो मुद्दा उठा रहे हैं क्या वह इतना बड़ा है कि सारी राजनीति उसी पर केंद्रित हो जाए। साफ लगता है कि उससे ज्यादा बड़े मुद्दे मौजूद हैं जिस पर सरकार को घेरा जा सकता था। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब की जानकारी उनकी तुलना में छोटा मुद्दा है बल्कि राज्य सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज्यादा व्यापक मुद्दे उठाकर सरकार को घेरा।प्रदर्शन का मामला हो तो प्रधानमंत्री का राज्यसभा में दिया भाषण और भी एकतरफा और कमजोर था। वे नेहरू विरोध का एक विमर्श चला रहे हैं जिसमें 2014 से एक काल विभाजन भी दिखाते हैं। इस बार उन्होंने और नीचे स्तर पर उतर कर इस विमर्श में यह भी जोड़ा कि इस परिवार ने गांधी उपनाम चुराया। उनके इस बार के भाषण से यह भी लगा कि अब उनकी (और जाहिर तौर पर भाजपा की) रणनीति गैर-कांग्रेसवाद की जगह नेहरू-गांधी परिवार को ही निशाना बनाने की है। इससे राहुल गांधी का महत्व बढ़ रहा है या घट रहा है इस सवाल पर भी विचार किया जाना चाहिए। लोक सभा में अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अगर भाजपा के निशिकांत दुबे को बोलने का अवसर दिया तो उन्होंने भी अनेक किताबें उद्धृत करके नेहरू को ही निशाना बनाया। अब लोक सभा तथा संसद के मंच का इस्तेमाल इस तरह के राजनैतिक एजेंडा के लिए होना कितना उचित है, इस सवाल को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो साफ है कि यह खराब राजनीति है। राहुल द्वारा उठाया मुद्दा भी हल्का है तो प्रधानमंत्री द्वारा दिया श्जवाबश उससे भी हल्का है।अगर राजनैतिक परिणामों की बात करें तो साफ है कि लोक सभा चलने न चलने की इस लड़ाई में पलड़ा फिलहाल विपक्ष और राहुल की तरफ झुका है। राहुल अपने साथ सारे विपक्ष को सदन से बाहर ले जाने में सफल रहे। और जब हफ्ता बीतने के बाद लोक सभा अध्यक्ष ने राहुल की जगह कांग्रेस के ही शशि थरूर को बोलने का अवसर दिया तो उन्होंने भी पहले राहुल को बुलाने की बात कहकर भाषण देने से मना कर दिया। हम जानते हैं कि इधर थरूर हर बात में कांग्रेस और राहुल को परेशान करने में ही आनंद महसूस करते थे और भाजपा का खेल खेलने के लिए जाने जाते थे। इतना ही नहीं विपक्ष लोक सभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहा है।

बांग्लादेश में बीएनपी की भारी जीत से भारत के लिए सियासी निहितार्थ

कमलेश

बांग्लादेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने फरवरी 2026 के संसदीय चुनावों में भारी जीत हासिल की है। उसने 300 सीटों में से 151 से 209 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। इससे बंगलादेश में बीएनपी की भारी जीत से भारत के लिए सियासी निहितार्थ स्पष्ट हैं, क्योंकि यह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग के पतन के बाद पहला बड़ा चुनाव है, जो 2024 के छात्र-आंदोलन से उभरा था। चूंकि बीएनपी पहले से सत्ता में रहती आई है, इसलिए उसकी जीत के वैश्विक मायने भी हैं। वह यह कि पार्टी कमोबेश पूर्व प्रधानमंत्री स्व.बेगम खालिदा जिया के अधूरे सपनों को ही साकार करेगी। वो भी तब जब उनके पुत्र तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। देखा जाए तो बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी को काफी पीछे छोड़ते हुए प्रचंड जीत दर्ज की है, जहां जमात को महज 42-68 सीटें ही मिलीं हैं। इसप्रकार तारिक रहमान, जो कि बीएनपी के प्रमुख नेता हैं, देश के संभावित प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बीएनपी की जीत की वजह यह है कि पार्टी ने गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार विरोध और विदेशी निवेश पर जोर दिया है। इससे भारत के लिए सियासी मायने भी साफ हैं। भले ही भारत-बीएनपी संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर पाकिस्तान और जमात से बीएनपी के पुराने गठजोड़ के कारण। इसलिए उनकी जीत से भारत को सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता और चरमपंथी समूहों की चिंता बढ़ सकती है, हालांकि बीएनपी समानता-आधारित संबंधों का वादा कर रही है। खासकर हसीना युग के बाद विदेश नीति में बदलाव से व्यापार, जल बंटवारा और कनेक्टिविटी पर असर पड़ सकता है। वहीं बीएनपी की जीत से दुनिया के लिए भी सियासी मायने साफ हैं। बीएनपी की जीत बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता ला सकती है, लेकिन विदेश नीति में संतुलन अपनाने से चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। वहीं दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक बदलाव संभव है, जहां भारत के प्रभाव में कमी और चीन के निवेश (+2.1 बिलियन) बढ़ सकता है। वैश्विक रूप से, यह क्षेत्रीय गठबंधनों को प्रभावित कर सकता है, खासकर म्यांमार शरणार्थी और आर्थिक सुधारों के संदर्भ में। यह ठीक है कि भारत और बीएनपी के बीच संबंध सुधारने के प्रयास चुनाव से पहले ही शुरू हो चुके हैं, जिसमें एस जयशंकर की तारिक रहमान से ष्बहुत मैत्रीपूर्णष चर्चा शामिल है। हालांकि हसीना के भारत में रहने से तनाव बरकरार है, फिर भी दोनों पक्ष सहयोग बढ़ाने को इच्छुक दिख रहे हैं। इसलिए संभावित सुधार के कदम उठाये जा सकते हैं। खासकर राजनयिक संपर्क बढ़ाना, क्योंकि भारत ने बीएनपी नेताओं से मुलाकातें कीं, जैसे प्रणय वर्मा की मीरजा फखरुल से, जहां बीएनपी ने भारत की सुरक्षा हितों का सम्मान करने का आश्वासन दिया। वहीं, व्यापार और वीजा बहाली के दृष्टिगत यात्रा, व्यापार और वीजा प्रतिबंध हटाने पर फोकस किया जा सकता है, जो हसीना के बाद बाधित हो गए थे। खासकर जल बंटवारा और सीमा मुद्दे हल करना यानी बीएनपी पानी बंटवारे और सीमा हत्याओं (जैसे फेलानी घटना) पर जोर दे रही है। इसलिए कुछ चुनौतियां भी आएंगी, क्योंकि बीएनपी हसीना की प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, जिसे भारत शरण दे रहा है, इससे जन-भावना भी प्रभावित हो रही है। वहीं, जमात-ए-इस्लामी का प्रभाव और पाक-चीन झुकाव भारत की चिंता बढ़ा सकता है। फिर भी भविष्य की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। चूंकि बीएनपी समानता-आधारित पड़ोसी संबंधों का वादा कर रही है, जबकि भारत अल्पसंख्यक सुरक्षा और चरमपंथ विरोध की शर्त रख रहा है। इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार, व्यावहारिक आवश्यकताएं रीसेट सुनिश्चित करेंगी, लेकिन ऐतिहासिक अविश्वास दूर करने में समय लगेगा। यद्यपि तारिक रहमान, जो बीएनपी के प्रमुख नेता हैं, और भारत के प्रति संयमित और तटस्थ रुख अपनाते दिख रहे हैं, जो अतीत के तनावपूर्ण रिश्तों से अलग है। वे समानता-आधारित पड़ोसी संबंधों पर जोर देते हैं, लेकिन शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखते हैं। उनका मुख्य स्टैंडपॉइंट्स यह है कि अल्पसंख्यक सुरक्षा और स्थिरता के नजरिए से वो अपने भाषणों में अहिंसा, कानून के राज और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया, जो भारत की चिंताओं को संबोधित करता है। वहीं, समानता का जोर के मद्देनजर ष्बारी के रिश्ते चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पुरानी असमानताओं (जैसे जल बंटवारा, सीमा हत्याएं) पर बात उठाई, लेकिन टकराव से बचते हैं। हाँ, भारत में शरण लेने वाली हसीना को वापस लाने की मांग, जो सबसे बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। हालांकि हालिया संकेत यही है कि ढाका लौटने के बाद उनके संयमित भाषण को खुफिया एजेंसियां इंडिया-न्यूट्रल मान रही हैं, जो

2001-06 के भारत-विरोधी दौर से अलग है। लिहाजा भारत के साथ सहयोग संभव, लेकिन पाकिस्तान-चीन झुकाव और जमात प्रभाव चिंता का विषय है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि व्यावहारिकता से रिश्ते सुधर सकते हैं। देखा जाए तो तारिक रहमान के हालिया भाषणों में भारत का सीधा जिक्र बहुत कम या न के बराबर आया है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। वहीं उनके भाषणों की मुख्य शैली में भारत का प्रत्यक्ष उल्लेख न करना समाहित है। खासकर ढाका लौटने (25 दिसंबर 2025) के 17 मिनट के पहले भाषण में भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन अल्पसंख्यक सुरक्षा (हिंदू, बौद्ध आदि), अहिंसा और कानून के राज पर जोर दियाकृजो भारत की प्रमुख चिंताओं को संबोधित करता है। वहीं, ष्बांग्लादेश फर्स्टष नारा यानी ष्ना दिल्ली, ना रावलपिंडी, सबसे पहले बांग्लादेशष कहकर तटस्थ विदेश नीति का संकेत दिया, जो पुराने भारत-विरोधी रुख से अलग है। उनके सकारात्मक संदेश साफ हैं। वो ये कि अंग्रेजी में अंतरराष्ट्रीय अपील की, समावेशी बांग्लादेश का खाका पेश किया, जो खुफिया एजेंसियों ने ष्री-अश्योरेंस सिग्नलष माना। देखा जाए तो उनके ये भाषण बीएनपी की री-ब्रांडिंग का हिस्सा हैं, जहां 2001-06 के भारत-विरोधी दौर से दूरी दिखाई गई। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह भारत के साथ संबंध सुधारने का रणनीतिक संकेत है, हालांकि हसीना प्रत्यर्पण जैसे मुद्दे लंबित हैं।

तंत्र में लोक को प्रतिष्ठित कीजिए

उमेश

हमने जिस प्रशासनिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, उसमें तंत्र की जवाबदेही लोक के प्रति है। हम चाहे जितना भी गर्व करें, लेकिन तंत्र की जवाबदेही के केंद्र में लोक की बजाय अभिजात्य है। यही वजह है कि संकट के क्षणों में हमारे तंत्र को लोक के प्रति जैसी त्वरित भूमिका निभानी चाहिए, वह निभाता नहीं दिखता। लेकिन यदि इसी तंत्र को पता चले कि लोक के बीच कोई अभिजात्य पहचान, महत्वपूर्ण नेता, उद्योगपति, सेलिब्रिटी आदि भी संकटग्रस्त है, हमारे तंत्र की प्रतिक्रिया त्वरित और गहन होती है। तंत्र की सोच की यह खोट ही है कि संकटग्रस्त आम आदमी के लिए त्वरित प्रतिक्रियाएं अपवादस्वरूप ही दिखती हैं। ऑर्ट ऑफ द स्टेट सिटी के रूप में विकसित हो रहे नोएडा में इंजीनियर युवराज के लापरवाही और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मेल से खोदे गए गहरे गड्ढे में डूबने से हुई मौत हो या फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ठीक बीच में जलनिगम के गड्ढे में गिरने से हुई कमल की मौत, भ्रष्टाचार और लापरवाही ही नहीं, तंत्र की सोच को भी जाहिर करती है। एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि नोएडा में गड्ढे में गिरे युवराज की जगह कोई आधुनिक शब्दावली में कहें तो किसी वीआईपी का बेटा होता, सेलिब्रिटी होता या फिर किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती का पारिवारिक होता तो क्या तंत्र उसी तरह खड़ा रहता, जिस तरह खड़ा रहा और युवराज डूब जाता। कुछ इसी अंदाज में एक बारगी सोचिए कि क्या दिल्ली के बीच में जलनिगम के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरे कमल की जगह कोई नेता पुत्र होता, किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी का बेटा होता या फिर किसी बड़े कारोबारी का बच्चा होता तो क्या पुलिस उसी तरह की प्रतिक्रिया करती, जैसा उसने इस मामले में किया। कमल के घर वालों ने देर रात ही पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस का आम दिनों की तरह कहना था कि सुबह आना। दिल्ली पुलिस का ध्येय वाक्य है, सदैव आपके साथ। लेकिन सदैव का उसका साथ सिर्फ वीआईपी के लिए होता है, आम लोगों के लिए नहीं। अगर पुलिस उसी समय सक्रिय हुई होती, उसने सीसीटीवी फुटेज देखे होते तो क्या वह कमल तक नहीं पहुंच जाती ? कमल के गड्ढे में गिरने की जानकारी एक राहगीर ने पास ही स्थित एक कैफे के सुरक्षा गार्ड को दी थी, सुरक्षा गार्ड ने जलबोर्ड कर्मी योगेश को जानकारी दी, योगेश ने ठेकेदार राजेश प्रजापति को फोन कर इसकी जानकारी दी। राजेश घटनास्थल पर आया, लेकिन पुलिस को किसी ने जानकारी नहीं दी। कैफे का गार्ड हो या फिर जलबोर्ड का कर्मी या फिर ठेकेदार, उन्होंने इस घटना को सामान्य तौर पर लिया। संजीदगी किसी ने नहीं दिखाई। सिर्फ इसलिए कि उनके चेतन-अवचेतन में कहीं न कहीं यह बात बैठी हुई है कि गिरने वाला कोई वीआईपी थोड़े ही है कि कुछ होगा। सभी ने सोचा कि देर रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। नागरिक हो या कर्मचारी या फिर तंत्र का जिम्मेदार तबका, उनकी ऐसी सोच हमारी सामाजिक और शासन व्यवस्था का कड़वा सच है। सवाल यह है कि क्या हमने लोकतंत्र की जो कल्पना की थी, उसके तहत ऐसी घटनाओं और ऐसी सोच की परिणति की कल्पना की थी? उदारीकरण के बाद हमने आर्थिक चमक-दमक को बढ़ाने के साथ ही शहरीकरण पर जोर दिया है। शहरीकरण ने आर्थिक लाभ-हानि की बुनियाद पर ही आगे बढ़ने वाली हमारी सोच को विकसित किया है। ग्रामीण सभ्यता वाले अपने देश को हम पूरी तरह शहरीकृत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शहर माने सभ्यता का पाठ हमने पढ़ लिया है और उसे ही हकीकत बनाने पर तुले हुए हैं। आधुनिक लोकतंत्र को अगर शहरीकृत लोकतंत्र कहें तो हैरत नहीं होनी चाहिए। शहरीकृत लोकतंत्र की अवधारणा को जाने-अनजाने हमारे मीडिया ने भी बढ़ावा दिया है। व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानने की बजाय हमने उसकी पृष्ठभूमि को अहम मान लिया है। मीडिया भी शहरों में होने वाली दुर्घटनाओं और घटनाओं को जब रिपोर्ट करता है तो वह हैरतअंगेज अंदाज में दिखाने की कोशिश करता है कि शहर में ऐसा हो गया तो बाकी देश का क्या हाल होगा। लोकतंत्र में वोट चाहे शहर के वोटर का हो या गांव के वोटर का, उसकी कीमत एक बराबर है। लेकिन जब यही लोकतांत्रिक व्यवस्था व्यक्तियों के साथ ट्रीटमेंट करने लगती है तो वह इस बराबरी की अवधारणा को भूल जाती है और फिर शहरी नागरिक को ग्रामीण लोक की तुलना में ज्यादा तरजीह देने लगती है। ऐसा करते वक्त उसे भान नहीं रहता कि भारत का समूचा इतिहास, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, ग्रामीण व्यवस्था केंद्रित रहा है। ऐसा नहीं कि गांवों में दुश्मनियां नहीं रहीं, लेकिन गांवों के सोच की बुनियाद आधुनिक शहर केंद्रित सोच की तुलना में हमेशा ज्यादा उदार रही। यह उदारता आधुनिक दौर में भी दिखती है। जब किसी गांव की नहर में कोई कार गिर जाती है तो पूरा गांव उस कार को निकालने दौड़ पड़ता है। जब नदी में कोई महिला आत्महत्या के लिए कूद जाती है तो वहां का लोक उसे बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देता है। कभी आग लग जाती है तो लोग वहां फायर ब्रिगेड का इंतजार नहीं करते, अपनी बाल्टी, कटोरे से ही आग बुझाने में जुट जाते हैं। गांधी भारतीय गांवों की इस गहन सोच को समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपने संविधान में व्यक्ति की बजाय गांवों को मूल इकाई बनाने का सुझाव दिया था। लेकिन चाहे बाबा साहब अंबेडकर हों या पंडित जवाहर लाल नेहरू, उन्होंने इसे दकियानुसी और पिछड़ी सोच बताते हुए खारिज कर दिया था। संविधान ने भारतीय नागरिक को व्यवस्था की मूल इकाई माना है। लेकिन इस इकाई का महत्व सिर्फ वोट हासिल करने के लिए होता है, जब ट्रीटमेंट का सवाल उठता है तो हमेशा लोक और आम पर वीआईपी, ग्रामीण पर शहरी को तरजीह दी जाती है। इसीलिए संकट के क्षणों में तंत्र की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती। जैसे ही तंत्र को पता चलता है कि संकट में वीआईपी है तो वह बिजली की गति से सक्रिय हो जाता है। सिर्फ राहत के लिए ही नहीं, वीआईपी की सहूलियत के लिए भी, लेकिन संकट ग्रस्त लोक होता है तो उसकी कई बार वह अनदेखी करता है, तो कई बार उस पर मिट्टी भी डाल देता है। नोएडा की घटना हो या दिल्ली का हादसा, उसने एक बार फिर तंत्र की इसी खामी की ओर इशारा दिलाया है। ऐसे हादसों की जांच होगी, ऐसी घटना ना हो, इसके लिए तंत्र की ओर कदम भी उठाए जाएंगे। दोषी और जवाबदेह लोगों को दंडित करने की बात भी होगी, लेकिन यहां भी पृष्ठभूमि का असर दिखेगा। अधिकारी बच जाएंगे और लीपापोती करने के लिए एकाध निचले तबके के कर्मचारी को दंडित कर दिया जाएगा। फिर इसे भुला दिया जाएगा, फिर तंत्र उसी ढर्रे पर काम करेगा, आने वाले कुछ दिनों में फिर वैसा हादसा होगा और फिर पुराने ढर्रे की तरह तंत्र काम करेगा। जब तक हम अपने तंत्र की सोच से वीआईपी को इरेज नहीं करेंगे, जब तक हम लोक को सही मायने में प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, जब तक नौकरशाही को लोक के प्रति जवाबदेह बनाने की सोच के साथ प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तंत्र में बुनियाद बदलाव संभव नहीं। आजादी की अस्सीवीं सालगिरह नजदीक आ रही है। इस मौके पर हमें पीछे मुड़कर देखना होगा और अपने तंत्र की सोच में मौजूद खामियों की ओर ध्यान देना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इस तरह सोचने और खामियों को दूर करके तंत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार हैं?

राहुल गांधी पर भाजपा का नया वार

विकास

कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भाजपा का डर अब खुलकर सामने आने लगा है। बुधवार को राहुल गांधी ने संसद में जिस तरह अमेरिका से हुए व्यापार समझौते और एपस्टीन फाइल्स पर मोदी सरकार को घेरा, उसके बाद उनके भाषण के कई हिस्से सदन की कार्रवाई से निकाल दिए गए। इसके बाद भी राहुल गांधी का सामना भाजपा नहीं कर पा रही है तो अब उन्हें संसद से बाहर करने की कोशिश करने लगी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को संसद में और संसद के बाहर कहा था कि भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। लेकिन गुरुवार को भाजपा ने सिर्फ लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की। समझा जाता है कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखे जाने पर भाजपा को अपने सहयोगी दलों से समर्थन की उम्मीद नहीं थी। दूसरा डर यह था कि इस पर संसद में बहस के दौरान फिर केंद्र बिंदु राहुल गांधी ही बनते। और मोदी सरकार नहीं चाहती कि राहुल गांधी पर बहस केंद्रित हो। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मैंने एक ठोस प्रस्ताव पेश किया है जिसमें मैंने उल्लेख किया है कि वे कथित तौर पर सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएआईडी से जुड़े हुए हैं और थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और अमेरिका जैसे स्थानों की यात्रा करते हैं, और भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं। मैंने मांग की है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए और उन्हें जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। अपने डर को छिपाने के लिए नरेन्द्र मोदी ने निशिकांत दुबे को आगे किया है, हालांकि इस नोटिस के बाद भाजपा को यह साबित भी करना होगा कि जिन फाउंडेशन्स या देशों का नाम लिया गया है, वे किस तरह देश विरोधी हैं और राहुल से उनके क्या संबंध हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकने और संसद सदस्यता खत्म करने का यह नोटिस उस समय दिया गया जब मोदी सरकार को ही यह साबित करना है कि एपस्टीन फाइल्स मामले में वह बेदाग हैं। क्योंकि नरेन्द्र मोदी, उनके केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, श्री मोदी के करीबी कारोबारी अनिल अंबानी जैसे लोगों के नाम इस कुख्यात मामले में आए हैं। ऐसे में केवल मुंहजबानी सफाई पेश करने से कुछ नहीं होगा। बल्कि ठोस सबूतों के साथ साबित करना होगा कि मानव तस्करी, यौन शोषण और मानवता को तार-तार करने वाले न जाने कितने घिनौने अपराधों से जुड़े इस मामले में किसी तरह भी मोदी सरकार का कोई संबंध नहीं है।हम यह बात पहले भी लिख चुके हैं कि इस मामले में दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं। किसी पर अपराध साबित हुआ या न हुआ हो, केवल एपस्टीन फाइल्स में नाम आने पर ही लोगों को इस्तीफे के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहां तक कि अमेरिका में भी इस पर ट्रंप के विरोधी नेता सवाल कर रहे हैं और उन्हें सवाल करने दिया जा रहा है। मगर भारत में भाजपा को बचाने के लिए एपस्टीन फाइल्स का नाम लेना ही गुनाह की तरह दिखाया जा रहा है। बुधवार को जब संसद के भीतर राहुल गांधी को इस मामले में बोलने से रोका गया तो उन्होंने बाहर आकर अपने आरोपों को दोहराया। जिसके बाद केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने प्रेस कांफ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। हालांकि वे चाहते तो जब से उनका नाम इस मुद्दे पर आया, तभी खुलकर सारी बातें बता सकते थे। लेकिन दबाने-छिपाने की इस प्रवृत्ति से ही शक गहराता है। बहरहाल, हरदीप सिंह पुरी ने माना कि उनकी मुलाकात कुख्यात अपराधी जेफ्री एपस्टीन से तीन-चार बार हुई थी। यानी राहुल गांधी ने संसद के भीतर जो कुछ कहा, उसे खुद हरदीप पुरी ने सत्यापित कर दिया है। इसके बाद उन पर क्या आरोप लगते हैं और कितने साबित होते हैं, ये तो बाद की बात है, सबसे पहले उन्हें नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार की डिक्शनरी में शायद नैतिकता शब्द है ही नहीं, इसलिए उसके आधार पर इस्तीफे भी नहीं होते।पत्रकारों को अपनी बात बताते हुए हरदीप पुरी ने कुछ बड़ी गलतियां कर दीं। एक तो उन्होंने कहा कि एपस्टीन पर कुछ कम उम्र की लड़कियों के शोषण का आरोप था, जबकि सच यह है कि इस मामले में उसे सजा भी हो चुकी थी। दूसरी बात कम उम्र की लड़कियों को ही बच्चियां कहा जाता है और यह बच्चियों की तस्करी, या उनसे दुष्कर्म बेहद गंभीर अपराध है। भारत में भी इसी पर पॉक्सो एक्ट बना है, लेकिन हरदीप पुरी ने इतने हल्के तरीके से यह बात कही, मानो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने ये दावा भी किया है कि मोदी कभी एपस्टीन से नहीं मिले, इस पर पवन खेड़ा ने पूछा है कि हरदीप पुरी आपको इतना यकीन कैसे है कि प्रधानमंत्री कभी श्री एपस्टीन से नहीं मिले? क्या आप उनके मध्यस्थ थे? क्या आप भाजपा नेताओं के लिए एपस्टीन के गेटकीपर थे?हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अमेरिका में भारतीय राजदूत के पद से रिटायर होने के

कुछ महीने बाद मुझे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट (आईपीआई) में आमंत्रित किया गया था। आईपीआई में मेरे बॉस टेरियल रोड लार्सन उस कुख्यात व्यक्ति, एपस्टीन को जानते थे। मैं तीन या अधिकतम चार बार उनसे मिला। आपको बता दूं कि जिस आईपीआई यानी अंतरराष्ट्रीय शांति संस्थान की बात हरदीप पुरी कर रहे हैं, वो न्यूयॉर्क का थिंक टैंक है, जहां हरदीप पुरी ने रिटायर होने के बाद और भाजपा में शामिल होने से पहले काम किया था। इस संस्था को भी एपस्टीन से फंड मिला था। हरदीप यह बात साफ नहीं कर रहे हैं कि अगर वो एपस्टीन से तीन-चार बार मिले तो क्या हर बार आईपीआई प्रतिनिधिमंडल के साथ मिले थे। लिंक्ड इन के संस्थापक रीड हॉफमैन का नाम भी इन फाइल्स में है और हरदीप सिंह पुरी की हॉफमैन से मुलाकात और उनके भारत दौरे की तैयारी की बात भी सामने आई है। हॉफमैन से मुलाकात पर एपस्टीन ने हरदीप सिंह पुरी से बातचीत की थी, ऐसा खुलासा भी हुआ है। ऐसे में सवाल है कि मोदी सरकार अपने दूतावास और विदेश मंत्रालय को छोड़कर सेवानिवृत्त हरदीप सिंह पुरी की सेवाएं क्यों ले रही थी और उन्हें इस नौकरी के बाद न केवल राज्यसभा सदस्यता, बल्कि मंत्री पद भी किस प्रभाव में नरेन्द्र मोदी ने दिया है। जबकि भाजपा में ही कई योग्य लोग मौजूद हैं।

पर्यटन विकास और सुरक्षा मानकों पर सरकार गंभीर, विधान परिषद में मंत्री जयवीर सिंह ने दिया विस्तृत ब्यौरा

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2026–27 के चौथे दिन विधान परिषद में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का विस्तारपूर्वक उत्तर देते हुए सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में नीतिगत और संरचनात्मक स्तर पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री ने ललितपुर, सीतापुर, झांसी और मिर्जापुर के धार्मिक स्थलों के विकास, होटल एवं रेस्तरां के सुरक्षा मानकों की जांच और दुरुस्तीकरण जैसे विषयों पर सदन को तथ्यात्मक जानकारी दी। ललितपुर जनपद की महरौनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नीलकंठेश्वर धाम और डोगरासन माता मंदिर के विकास संबंधी प्रश्न पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि नीलकंठेश्वर धाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, इसलिए वहां किसी भी प्रकार का विकास कार्य संबंधित विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग केवल उन्हीं स्थलों पर कार्य करता है जहां बजट की उपलब्धता के साथ निर्विवाद और निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो।सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक स्थित प्राचीन गंगा सागर तीर्थ रामेश्वर धाम के जीर्णोद्धार संबंधी प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि विभाग की वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार केवल मूलभूत पर्यटक सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और साइनेज का विकास किया जाता है। जीर्णोद्धार, मरम्मत या लाइटिंग से जुड़े कार्य वर्तमान मानकों के अंतर्गत अनुमन्य नहीं हैं।झांसी जनपद के अंजनी माता मंदिर, राम जानकी मंदिर सगौली और मऊरानीपुर स्थित श्री मढ़ा सरकार प्राचीन मंदिर के पर्यटन विकास पर मंत्री ने कहा कि इन स्थलों का विकास विभागीय गाइडलाइन और बजट के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य क्षेत्रीय धार्मिक पर्यटन को सशक्त पहचान देना है।मिर्जापुर नगर के 100 वर्षीय श्री चित्रगुप्त मंदिर और चित्रगुप्त घाट को गंगा के कटाव से बचाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर मंत्री ने बताया कि यह विषय पर्यटन विभाग की गाइडलाइन के दायरे में नहीं आता। हालांकि पर्यटन निदेशालय द्वारा इस संबंध में सिंचाई विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित कर दिया गया है, ताकि मंदिर और घाट की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।होटल और रेस्तरां में सुरक्षा मानकों के संबंध में मंत्री ने स्पष्ट किया कि होटलों का पंजीकरण सराय एक्ट के तहत जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है, जबकि बार और रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग के अधीन नहीं आते। उन्होंने बताया कि सुरक्षा मानकों की नियमित जांच पुलिस, अग्निशमन विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाती है, जिससे पर्यटकों को सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण मिल सके।सीतापुर के महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी धाम के विकास पर मंत्री ने जानकारी दी कि 10 नवम्बर 2022 के शासनादेश के अंतर्गत 87.01 लाख रुपये की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी।

राजवाहा सिकंदरपुर पुनर्स्थापना परियोजना के लिए 40 लाख रुपये की अवशेष धनराशि जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश सरकार ने सिंचाई खंड हाथरस के कार्य क्षेत्र में आने वाले राजवाहा सिकंदरपुर के किलोमीटर 0.00 से 11.840 तक पुनर्स्थापना एवं नहरी भूमि सीमांकन परियोजना कार्य के लिए 40 लाख रुपये की अवशेष धनराशि अवमुक्त कर दी है। इस संबंध में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है।जारी आदेश के अनुसार यह धनराशि परियोजना के शेष कार्यों को गति देने और निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण कराने के उद्देश्य से जारी की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि नहर तंत्र को सुदृढ़ बनाकर किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सके तथा नहरी भूमि का स्पष्ट सीमांकन सुनिश्चित हो।शासनादेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि परियोजना के अंतर्गत कराए जाने वाले सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और तय समयसीमा में पूर्ण कराए जाएं। इसके लिए संबंधित मुख्य अभियंता को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभागीय अधिकारियों को भी कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा प्रगति रिपोर्ट समय–समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।प्रदेश सरकार ने कहा है कि सिंचाई व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। राजवाहा सिकंदरपुर परियोजना को क्षेत्रीय कृषि विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

संक्षिप्त खबरें

राजकीय आईटीआई अलीगंज में ऑटोमोटिव सेक्टर के दो जॉब रोल में निःशुल्क प्रशिक्षण

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, लखनऊ द्वारा युवाओं के कौशल उन्नयन एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), अलीगंज, लखनऊ में ऑटोमोटिव सेक्टर के अंतर्गत दो जॉब रोल में निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य आवंटित किया गया है। इनमें 'ऑटोमोटिव असेम्बली ऑपरेटर' (320 घंटे) तथा 'इलेक्ट्रिक व्हीकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन' (420 घंटे) शामिल हैं।प्रभारी कौशल विकास कार्यालय एस.पी. निगम ने जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं, 12वीं अथवा आईटीआई उत्तीर्ण या अध्ययनरत अभ्यर्थी, जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा दो पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ किसी भी कार्य दिवस में संस्थान के कक्ष संख्या–08 में उपस्थित होकर ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।प्रशिक्षण हेतु प्रवेश उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 'प्रथम आओ, प्रथम पाओ' के आधार पर दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को रोजगार एवं सेवायोजन के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें उद्योगों में प्रत्यक्ष रोजगार से जोड़ा जा सके।इन पाठ्यक्रमों में महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पृथक सीटें आरक्षित की गई हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में संस्थान के कौशल विकास कार्यालय के मोबाइल नंबर 7785956549 पर संपर्क कर सकते हैं।

विधानसभा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पुरस्थापित

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने विधानसभा के बजट सत्र 2026–27 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2026 को सदन में पुरस्थापित किया। उन्होंने दोनों विधेयकों को प्रस्तुत करते हुए सदन से इन्हें पुरस्थापित करने की अनुमति देने का आग्रह किया।प्रस्ताव पर सदन में मत व्यक्त कराया गया, जिसमें बहुमत से दोनों विधेयकों को पुरस्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान की गई। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रस्तावित संशोधनों पर आगे की विधायी प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हो गया है।उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन संशोधन विधेयकों के माध्यम से विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, सुचारु प्रशासनिक व्यवस्था और आधुनिक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराना है। इन संशोधनों से विश्वविद्यालयों में जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ेगी तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की स्थिति और मजबूत होगी।

एआईएमआईएम सिर्फ मुस्लिमों की नहीं, सभी हिंदुस्तानियों की पार्टी : इमरान बंटी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, 14 फरवरी। यूपी के जौनपुर में ऑल इंडिया मजलिस–ए– इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के जिलाध्यक्ष इमरान बंटी ने पार्टी को लेकर प्रचलित धारणा को निराधार बताया है। शनिवार को पत्रकारो से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि एआईएमआईएम को केवल मुस्लिम समाज की पार्टी कहना गलत और भ्रामक है। बंटी ने कहा कि एआईएमआईएम सभी हिंदुस्तानियों की पार्टी है और समाज के हर वर्ग की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति अपने हक और मुद्दों की बात करता है तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल उसे 'वोट काटने वाला' बताकर जनता को गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मुस्लिम समाज सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिये पर है। संवैधानिक पदों पर बैठे कुछ लोगों द्वारा की जाने वाली टिप्पणियों से अल्पसंख्यक समाज में भय का वातावरण बनता है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं तो उन्हें अनावश्यक रूप से विवादित बताया जाता है। आगामी जिला पंचायत चुनाव को लेकर बंटी ने घोषणा की कि पार्टी 50 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने दावा किया कि एआईएमआईएम के समर्थन के बिना जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आसान नहीं होगा। साथ ही बताया कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्वांचल संयुक्त सचिव जावेद सिद्दीकी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

अतुल्य वेल्फेयर ट्रस्ट द्वारा पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, लगाए गए पौधे

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर।अतुल्य वेल्फेयर ट्रस्ट द्वारा पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यह कार्यक्रम शनिवार को पार्थ ग्लोबल स्कूल, रुहट्टा में आयोजित किया गया, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों, छात्रों, शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान, शहीदों की याद में कैंडल जलाकर मौन रखा गया। इसके अतिरिक्त, सभी सदस्यों ने वृक्षारोपण कर अमर सपूतों को नमन किया। अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक संगठन के विधिक सलाहकार राजबहादुर पाल और सूबेदार मेजर बी.एन. दुबे ने वृक्षारोपण के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजबहादुर पाल ने कहा कि सेना के सिपाही का बलिदान समाज पर एक ऋण है। उन्होंने मां भारती के अमर वीर सपूतों को शत–शत नमन करते हुए कहा कि पुलवामा का त्याग आतंकवाद के विरुद्ध हम सभी को एकजुट करता है। भूतपूर्व सैनिक राजबहादुर पाल ने बच्चों के साथ अपने कारगिल युद्ध के अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने घायल होने के बावजूद युद्ध जारी रखा था। उन्होंने अपनी और अन्य सैनिकों की वीरगाथाएं सुनाईं और बच्चों को देश के शौर्य और पराक्रम को जानने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की प्राचार्या डॉ. शिप्रा सिंह ने कहा कि सैनिकों की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। मेजर सूबेदार बी.एन. दुबे ने पुलवामा में जान गंवाने वाले सभी वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हम उनके और उनके परिवारों के सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे। उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू–कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की बस पर हमला किया था। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। जैश–ए–मोहम्मद के एक आतंकी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ की बस को टक्कर मार दी थी। इस घटना के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ व्यापक गुस्सा देखा गया था।

संक्षिप्त खबरें

पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहने देगी सरकार : नरेन्द्र कश्यप

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने विधानसभा के बजट सत्र 2026–27 के दौरान प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि योगी सरकार पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं के शैक्षिक हितों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 2 लाख रुपये निर्धारित है, जिसे पूर्व सरकार के समय 1 लाख रुपये से बढ़ाया गया था और वर्तमान सरकार इसे निरंतर जारी रखे हुए है।मंत्री कश्यप ने सदन को अवगत कराया कि वर्ष 2023–24 से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के एक भी पात्र छात्र–छात्रा को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार घोषणाओं के बजाय धरातल पर कार्य करने में विश्वास रखती है और छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान विभाग का बजट लगभग 1,286 करोड़ रुपये था, जबकि वर्तमान सरकार में इसे बढ़ाकर करीब 3,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो लगभग तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है। मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 38 लाख छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और विभागीय नियमों के अनुसार एक भी पात्र छात्र–छात्रा को वंचित नहीं रखा जाएगा।

आईटीआई अलीगंज में 'दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0' के तहत रोजगार मेला

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित "दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0" के तहत गुरुवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), अलीगंज, लखनऊ में दिव्यांगजन रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य दिव्यांग अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों से जोड़ते हुए उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना था।जिला समन्वयक राज कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार मेले में 16 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। इन कंपनियों द्वारा कुल 1000 से अधिक रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। कार्यक्रम में 105 दिव्यांग अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और विभिन्न पदों के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की।साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 23 अभ्यर्थियों का यथास्थान चयन किया गया, जबकि अन्य अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए संबंधित कंपनियों द्वारा विचाराधीन रखा गया है। आयोजन के दौरान अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया गया, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकें। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के रोजगार मेले दिव्यांगजन सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अभियान के माध्यम से दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महानगर क्षेत्र में जागरूकता अभियान

लखनऊ, (संवाददाता)। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 12 फरवरी 2026 को थाना महानगर की पिंक बूथ 79 टीम द्वारा न्यू हैदराबाद पिंक बूथ के पास महिलाओं और स्कूली बच्चों को महिला अपराध, साइबर क्राइम तथा अपराध से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से "जागरूकता जगाएं, मिशन शक्ति से जुड़ें, सुरक्षित और सशक्त समाज बनाएं" का संदेश दिया गया।मिशन शक्ति 5.0 के तहत पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ के 54 थानों पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। प्रत्येक केंद्र पर एक निरीक्षक, एक अतिरिक्त निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक तथा एक महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की गई है, ताकि थानों पर आने वाली महिलाओं की समस्याओं का त्वरित और संवेदनशील निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।न्यू हैदराबाद क्षेत्र में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 20 से 25 महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। पिंक बूथ 79 थाना महानगर की महिला हेड कांस्टेबल अंजली यादव और महिला कांस्टेबल सुनीता कुमारी ने प्रतिभागियों को उनके कानूनी अधिकारों, महिला अपराधों से बचाव, साइबर अपराध की पहचान और उससे सुरक्षा के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सीईआईआर पोर्टल और यूपी कॉप ऐप के उपयोग के बारे में भी बताया गया।प्रतिभागियों को आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों 1090 (महिला पावर लाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 108 (एम्बुलेंस), 1098 (चाइल्डलाइन) और 1076 (टोल–फ्री हेल्पलाइन) की जानकारी दी गई तथा बताया गया कि 1090 पर शिकायत करने पर पहचान गोपनीय रखी जाती है। छात्राओं को समझाया गया कि डरने से अपराध कम नहीं होते, बल्कि समय पर शिकायत करने से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई संभव होती है। उन्हें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न या साइबर परेशानी की स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।मिशन शक्ति 5.0 के तहत स्थापित पिंक बूथों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को एक सुरक्षित, संवेदनशील और सहज वातावरण उपलब्ध कराना है, जहां वे बिना किसी झिझक अपनी समस्याएं दर्ज करा सकें। इन बूथों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी तैनात की जाती हैं, जिन्हें महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशील संवाद और मनोवैज्ञानिक सहयोग का प्रशिक्षण दिया गया है। ये बूथ एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला सुरक्षा केंद्रों और विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं से सीधे जुड़े हैं।

निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल के विरोध में प्रदेशभर में बिजली कर्मियों का उग्र प्रदर्शन

लखनऊ, (संवाददाता)। पावर सेक्टर के निजीकरण और प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में बिजली कर्मियों ने व्यापक स्तर पर कार्य बहिष्कार कर जोरदार प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों के अनुसार प्रदेश के सभी जनपदों में बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर अपने–अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आंदोलन के दौरान प्रदेशभर में कार्य ठप रहा और कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के विरुद्ध एकजुटता प्रदर्शित की।संघर्ष समिति ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उत्तर प्रदेश में जारी निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल निरस्त नहीं किया गया और निजीकरण के लिए टेंडर जारी किया गया, तो प्रदेश के सभी बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर सामूहिक रूप से 'जेल भरो आंदोलन' प्रारंभ करेंगे। समिति ने कहा कि इस स्थिति में उत्पन्न होने वाली समस्त परिस्थितियों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। कर्मचारियों ने यह भी ऐलान किया कि यदि संसद के बजट सत्र में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल को पारित करने का प्रयास किया गया तो देशभर के लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के तत्काल प्रभाव से 'लाइटनिंग स्ट्राइक' पर चले जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी।आंदोलन के दौरान पावर सेक्टर के निजीकरण का विरोध करते हुए कर्मचारियों ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 तथा प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में चल रही निजीकरण प्रक्रिया को निरस्त करने और बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया गया। संघर्ष समिति का कहना है कि निजीकरण से बिजली व्यवस्था की सामाजिक जवाबदेही समाप्त हो जाएगी और आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।संघर्ष समिति ने बताया कि पहली बार बिजली कर्मचारियों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा और दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी सक्रिय भागीदारी की। बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों, मजदूर संगठनों और किसानों की संयुक्त एकजुटता ने इस आंदोलन को व्यापक स्वरूप दिया है। राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर आयोजित विशाल प्रदर्शन में संयुक्त किसान मोर्चा के एकादशी यादव और दिनेश रावत ने भी संबोधित किया और बिजली क्षेत्र के निजीकरण को जनविरोधी बताया। वक्ताओं ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास देश के किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के हितों के खिलाफ है।संघर्ष समिति ने यह भी आरोप लगाया कि पावर सेक्टर में नियमित प्रकृति के कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग की जा रही है, जिससे न केवल कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा प्रभावित हो रही है बल्कि विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और उपभोक्ता सेवा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। समिति की प्रमुख मांगों में आउटसोर्सिंग पर तत्काल रोक, रिक्त नियमित पदों पर सीधी भर्ती तथा कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का नियमितीकरण शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण के माध्यम से वितरण, उत्पादन और टीबीसीबी के जरिए ट्रांसमिशन को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया गरीब उपभोक्ताओं, छोटे एवं मध्यम उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।प्रदेश के सभी जिलों में शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से हुए इस व्यापक प्रदर्शन ने यह संकेत दे दिया है कि बिजली कर्मी निजीकरण के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार हैं।

अज्ञात ट्रक की टक्कर से 82 वर्षीय साइकिल सवार की मौत, चालक फरार

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के सैरपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 82 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना 12 फरवरी 2026 को लगभग 14रू10 बजे छठा मिल के पास सीतापुर रोड पर हुई, जहां एक अज्ञात ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को पीछे से टक्कर मार दी और चालक वाहन समेत फरार हो गया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा–तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए।थाना सैरपुर को घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ में सामने आया कि बुजुर्ग व्यक्ति साइकिल से जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे के बाद चालक बिना रुके वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।मौके पर पहुंचे परिजनों ने मृतक की पहचान राम चन्द्र लोधी पुत्र स्वर्गीय गरीबे लोधी, निवासी सरैंया, थाना बीकेटी, जनपद लखनऊ के रूप में की। उनकी उम्र लगभग 82 वर्ष बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल हो गया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूरी की और पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि फरार ट्रक और उसके चालक की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अज्ञात वाहन चालक की तलाश के लिए विशेष टीम लगाई गई है और शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

जिला चिकित्सालय व महिला चिकित्सालय दलालों के शिकंजे में, शहर में अवैध अस्पतालों की भरमार

अयोध्या।जिला पुरुष चिकित्सालय व जिला महिला चिकित्सालय के साथ–साथ नगर के गली, कूचो, मुहल्लों, कालोनियों में संचालित अवैध से संचालित अस्पतालों निजी क्लीनिकों के ऊपर पुराने सीएमओ की तरह अभी कुछ दिन पहले आए नए सीएमओ डॉ देवेन्द्र कुमार का ध्यान नहीं जा रहा है।जबकि देखा जाए तो जिला पुरुष चिकित्सालय के साथ–साथ जिला महिला चिकित्सालय पर अपना इलाज करने आने वाले मरीजों के साथ अच्छी खासी धन उगाही वहां पर सक्रिय दलालों के अलावा कमीशन के नाम पर महंगे महंगी दवाइयां भी लिखने से वहां पर तैनात चिकित्सक दिखाई देते हैं।अभी कुछ दिन पहले जिला पुरुष चिकित्सालय में ब्लड बैंक के नाम पर अच्छी खासी वसूली के मामले भी आए हुए थे और जिस पर इससे संबंधित कर्मियों पर कार्यवाही भी हुई थी। इससे बुरा हाल जिला महिला चिकित्सालय का है देखा जाए तो वहां पर जिला अस्पताल के सामने संचालित निजी क्लीनिक तथा अस्पतालों पर कार्य महिला कर्मी अपना डेरा सुबह से लेकर देर रात तक जिला अस्पताल में डाले रहती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य जिला महिला चिकित्सालय में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को किसी तरह बहला फुसलाकर निजी चिकित्सालय की ओर ले जाना होता है अभी कुछ माह पहले प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय ने सामने स्थित प्राइवेट क्लीनिक पर काम करने वाली महिला कर्मियों को सूचना पर पड़ा था। जिला पुरुष चिकित्सालय के साथ–साथ जिला महिला चिकित्सालय में इस तरह का खेल चलता ही है साथ ही साथ शहरके गलियों, मोहल्लों कॉलोनियों में खुले अवैध रूप से संचालित क्लीनिक, अस्पतालों पर आखिर कब नये सीएमओ साहब डाक्टर संदीप कुमार कार्यवाही कब करेंगे? स्थानीय लोगों का कहना है कि सीएमओ साहब जिले के ग्रामीण अंचलों में सिर्फ छापा मार कर कार्यवाही करने में जुटे हुए हैं जबकि शहर के कई ऐसे मोहल्ले तथा गलियों हैं, जहाँ पर अवैध रुप संचालित अस्पताल व क्लीनिक तो है लेकिन वहां पर एंबुलेंस तो छोड़िए यहाँ पर कार तक नहीं जा सकती है। शहर के अति व्यस्ततम इलाका नाका के आसपास स्थित कई प्रतिष्ठित अस्पताल मुख्य मार्ग पर स्थित है।यहां पर इलाज करने आने वाले मरीज व उनके तीमारदार दो पहिया बाहन व चार पहिया वाहन मार्ग पर ही खड़ा कर देते है, जिसके चलते इस मार्ग पर सुबह से लेकर देर रात तक जाम लगा रहता है।वही शहर के हैदरगंज,वजीरगंज, कसाबबाड़ा जनौरा, रिकाबगंज, निगावां, मछली मंडी, सा हबगंज, बेनीगंज, कोरखाना, धनीराम का पुरवा सहित कई ऐसे मोहल्ले व कलोनिया है।जहाँ पर हस्पिटल, नर्सिंग होम व क्लीनिक संचालित है।इनके संचालक वहाँ पर आने वाले मरीजों से चिकित्सा के नाम पर पैसे भी वसूल रहे हैं लेकिन सुविधा देखी जाए तो कुछ नहीं है। कहीं–कहीं तो ऐसे नर्सिंग होम, हॉस्पिटल व क्लीनिक है।जहां पर एंबुलेंस तो छोड़िए कार तक के जाने का रास्ता नहीं है। सवाल यह उठता है कि अगर इन जगहों पर नर्सिंग होम क्लीनिक खुले हैं तो संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे मिल रहा।वहीं कुछ ऐसे नर्सिंग होम, हस्पिटल व क्लीनिक इन गलियों में खुले हुए हैं जिनके पास संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं है।जिसपर सीएमओ डा० देवेन्द्र का नजर नहीं जा रहा है।

सीओ सिटी व महिला एसओ ने चलाया चेकिंग अभियान

अयोध्या। वैलेंटाइन डे पर नगर पुलिस तथा महिला थाना पुलिस ने गुलाब बाड़ी सहित अन्य स्थानों तथा रेस्टोरेंट पर चेकिंग अभियान चलाया इस मौके पर सीओ सिटी श्रेयश त्रिपाठी ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अश्वनी पांडे के साथ गुलाब बाड़ी के अलावा प्रमुख पार्कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन निरीक्षण किया।वहीं महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने प्रमुख पार्कों में व

अन्य चौराहों पर 'मिशन शक्ति फेज 5.0' के तहत वहां पर मिले युवतियों व बालिकाओं को पोस्ट व पंपलेट के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दिया। इस मौके पर उनके अलावा उप निरीक्षक प्रिया, पीआरडी शीलू, पीआरडी ललिता द्वारा गुलाब बाड़ी व चौक जनपद अयोध्या में जाकर शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या योजना ,बाल विवाह मुक्त भारत अभियान और हेल्पलाइन नंबर के बारे में बालिकाओं /महिलाओं को जागरूक किया गया।

संक्षिप्त खबरें

आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक कैंट रेलवे स्टेशन ने चलाया जागरूकता अभियान

अयोध्या। रेल मित्र अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कैंट रेलवे स्टेशन हरीश शाही ने शुक्रवार को मसौधा – भरतकुंड, अयोध्या कैंट–सलारपुर रेल मार्ग पर जागरूकता अभियान चलाया।इस मौके पर उन्होंने रेलवे लाइन के किनारे बसे लोगों, राहगीरों व बच्चों , महिलाओं, आस पास पड़ने वाले स्कूलों के छात्रों को उक्त एरिया के वार्ड मे सदस्य, पार्षद प्रधान, स्कूलों के प्राध्यापक आदि की मौजूदगी में सभी को रेलवे लाइन पर ना आने, रेल लाइन क्रॉस ना करने, लाइन के किनारे पतंग बाजी ना करने तथा ओएचई पोलो व उनके इंसुलेटर पर के साथ साथ आने जाने वाली ट्रेनों पर

पत्थर न मारने के लिए समझाया।परिजनों तथा उनके बच्चों को समझाया कि ट्रेनों पर पत्थर मारने से ट्रेन ड्राइवर व गार्ड जो ट्रेनों के परिचालन का कार्य करते हैं तथा यात्रियों को चोट लगने की प्रबल संभावना रहती है तथा रेल संपत्ति को भारी नुकसान होने के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया।

अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कथित पुलिस वसूली से यात्रियों में नाराजगी

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर तैनात कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित रूप से अवैध वसूली किए जाने की शिकायतों ने यात्रियों के बीच असंतोष पैदा कर दिया है। स्टेशन पर आने–जाने वाले यात्रियों का आरोप है कि जांच और पूछताछ के नाम पर उनसे अनावश्यक रूप से पैसे मांगे जा रहे हैं।यात्रियों के अनुसार, देर रात आने वाली ट्रेनों से उतरने वाले बाहरी यात्रियों और छोटे व्यापारियों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। कई लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मामूली कारण बताकर उन्हें रोका जाता है और चालान या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर नकद राशि वसूली जाती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इससे शहर की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, खासकर तब जब अयोध्या धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यात्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि स्टेशन परिसर में पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए और सीसीटीवी फुटेज की निष्पक्ष जांच कराई जाए।हालांकि, संबंधित पुलिस अधिकारियों की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार, मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों तक पहुंचा दी गई है और यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।जनता ने जिला प्रशासन और रेलवे प्रबंधन से अपील की है कि यात्रियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का विश्वास बना रहे।

माध्यमिक शिक्षक संघ पाण्डेय गुट के जिलाध्यक्ष बने वीरेन्द्र बहादुर सिंह,भाजपा नेताओं ने दी बधाई

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। भाजपा नेता व शिक्षक नेता वीरेन्द्र बहादुर सिंह को आदर्श इंटर कालेज में सम्पन्न हुए चुनाव में माध्यमिक शिक्षक संघ पाण्डेय गुट का लगातार पांचवीं बार जिलाध्यक्ष चुने जाने पर शिक्षकों और समर्थकों में उत्साह देखा गया।सिविल लाइन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की।समर्थकों ने कहा कि उनके नेतृत्व में संगठन ने शिक्षकों की समस्याओं को मजबूती से उठाया है और कई मुद्दों का समाधान कराया है। यही कारण है कि शिक्षकों ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है।इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व नेताओं ने भी बधाई दी। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि वीरेन्द्र बहादुर सिंह एक कर्मठ और जुझारू नेता हैं। उनके नेतृत्व में शिक्षक संगठन लगातार मजबूत हुआ है और शिक्षकों की आवाज को प्रभावी ढंग से शासन–प्रशासन तक पहुंचाया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगे भी वे शिक्षकों के हितों के लिए सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे।महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह पुनर्निर्वाचन उनके कार्यों की स्वीकृति है। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और समन्वय के बल पर शिक्षकों के बीच विश्वास कायम किया है। पार्टी को भी ऐसे समर्पित नेतृत्व पर गर्व है।पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सहित अन्य नेताओं ने भी शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। वीरेन्द्र बहादुर सिंह ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए शिक्षक हितों के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया।अभिषेक मिश्र, अवधेश पाण्डेय 'बादल', शैलेन्द्र कोरी, तिलकराम मौर्य, इंद्रभान सिंह, अखंड सिंह डिम्पल, राघवेन्द्र पाण्डेय, सुनील तिवारी शास्त्री, व्यापारी नेता शिवम शुक्ला, दिवाकर सिंह और राजेश सिंह सहित अन्य नेताओं ने उनके पुनरु जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

पाली थाना क्षेत्र के मुड़रामऊ में डिप्टी कमिश्नर के भाई की हुई हत्या,जांच में जुटी पुलिस'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' शनिवार को पाली थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़रामऊ में सुबह एक युवक घायल अवस्था में खून से लथपथ अपने घर में पड़ा मिला, पड़ोसी की सूचना पर पहुंची पुलिस एवं ग्रामीणों ने एंबुलेंस से उसे पाली पीएचसी भेजा, गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जहां उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने गांव के ही दो लोगों पर पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है,जानकारी के मुताबिक युवक के पिता की बीते लगभग ढाई साल पहले हत्या कर दी गई थी। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार पाली थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़रामऊ में विजय प्रकाश (35) पुत्र स्व0 दयाराम राठौर अपनी मां गोमती के साथ रहता था, उसका भाई रामेंद्र मथुरा में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात है। ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 5. 30 बजे विजय प्रकाश पड़ोस में रहने वाले सुशील मिश्रा के घर में घुसा और गांव के ही इन्द्रपाल एवं नरेश के नाम लेकर कह रहा था कि वह लोग उसकी हत्या कर देंगे, उसके घर में गंडासा लिए बैठे हैं। इसके बाद वह सुशील मिश्रा के घर पर लगे पेड़ पौधों के बीच लेट गया। सुशील मिश्रा ने विजय प्रकाश को उसकी मां गोमती के साथ मिलकर घर पहुंचाया और वह नित्य क्रिया में व्यस्त हो गए। करीब आधा घंटा बाद रोने चीखने की आवाज सुनकर सुशील मिश्रा व अन्य ग्रामीण विजय प्रकाश के घर पहुंचे तो देखा कि विजय प्रकाश खून से लथपथ अपने आंगन में पड़ा था और उसकी आंतें बाहर निकल आई थी। सुशील मिश्रा ने पाली थाना पुलिस सहित एंबुलेंस को फोन किया, सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल अवस्था में विजय प्रकाश को एंबुलेंस से पाली पीएचसी भेजा, जहां से उसे गंभीर हालत होने के कारण हरदोई रेफर कर दिया गया। हरदोई में इलाज के दौरान विजय प्रकाश ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि विजय प्रकाश अविवाहित था। मृतक की मां गोमती ने गांव निवासी महावीर और समरपाल के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों से मृतक के परिवार की पुरानी रंजिश चल रही है।

फोरलेन बनने के बावजूद भी नहीं चल रही दशकों से अयोध्या से रायबरेली के लिए रोडवेज बस

अयोध्या।केंद्र व राज्य सरकार अयोध्या के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।देखा जाए तो अयोध्या में राम मंदिर बनने की चलते यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की आवाजाही आई के चलते केंद्र व राज्य सरकार ने हवाई रेल तथा सड़क मार्ग पर चलने वाले साधनों में काफी बढ़ोतरी किया है।श्रद्धालुओं को रामनगरी आने को आकर्षित करने के लिए हवाई जहाज ट्रेनों के साथ–साथ सामान्य, वातानुकूलित तथा इलेक्ट्रिक बसों में भी बढ़ोतरी किया है। इसके बावजूद आज भी अयोध्या रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन होने के बावजूद आज भी इस मार्ग पर रायबरेली के लिए एक अनुबंधित बस जो सुबह जाती है वही शाम को देर शाम वापस होकर अयोध्या डिपो पर आती है। जबकि देखा जाए जगदीशपुर के पहले कुमारगंज थाना भी है इनायत नगर थाना भी है वही जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते यहां पर आने जाने वाले बस यात्रियों को या तो मजबूरी में अधिक पैसे देकर प्राइवेट बसों का सहारा लेना पड़ता है या फिर माया का सहारा वह भी दो से तीन जगह बदलना पड़ता है परंतु इस गंभीर समस्या पर रोडवेज विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। बताते चले अयोध्या से जगदीशपुर राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन के रूप में बना हुआ है।बारून के पास टोल भी लग चुका है लेकिन पता नही किस कारण अभी तक रोडवेज विभाग का ध्यान इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपने सरकारी बस चलवाने का नही हो रहा है।अयोध्या से रायबरेली जाने वाली फोर लेन सड़क अयोध्या जिले के सैकड़ों गांवों दर्जनो बाजारों व कृषि विवि कुमारगंज से होकर गुजरती है, इस रोड पर केवल निजी वाहन ही चलते है या टैक्सियों में ऑटो, मैजिक या प्राइवेट बस है। जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।रोडवेज विभाग आखिरकार बस संचालन क्यों नही कर पा रहा है।मार्ग के किनारे रहने वाले व इस मार्ग पर चलने वालों का कहना है कि कई माह से सड़क बन चुकी है,लेकिन सरकारी बस का दर्शन नही हो रहा है।जिससे हजारों लोगों को आवागमन करने के लिए सुल्तानपुर व बाराबंकी से घूम कर जाना होता है। जबकि इस सड़क से रोडवेज बस चलने से हजारों लोगों को प्रतिदिन फायदा होगा। अयोध्या जिले के रानी बाजार, कुचेरा बाजार, मिल्कीपुर, इनायतनगर, बारून बाजार, कुमारगंज सहित हलियापुर, थौरी सहित जगदीशपुर को जाने वाले हाइवे पर रोडवेज की बसें नहीं चलने से परेशानी। रोडवेज के एआरएम आदित्य प्रकाश ने बताया कि रायबरेली रोड पर तिलोई के पास पुलिया नही बनी है जिसके कारण रोडवेज की बसों का संचालन नही हो पा रहा है।

संक्षिप्त खबरें

शिवरात्रि पर्व को लेकर महापौर एवं नगर आयुक्त ने नागेश्वर नाथ एवं श्रीरेश्वरनाथ मंदिर परिसर का किया निरीक्षण

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। रविवार को शिवरात्रि के मौके पर रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम ने कार्य योजना बना ली है। महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने नगर आयुक्त जयंत कुमार के साथ नागेश्वरनाथ मंदिर एवं श्री क्षीरेश्वर नाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्था संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उनके साथ अपर नगर आयुक्त भारत भार्गव, जोनल अधिकारी अशोक गुप्त, सहायक अभियंता सिविल राजपति यादव भी थे।महापौर ने सबसे पहले नागेश्वरनाथ मंदिर का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर परिसर जाने वाले रास्ते पर मैट बिछाने, अन्य स्थानों पर लगातार सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की तैनाती करने, स्वागत बोर्ड बदलवाने तथा मंदिर परिसर के आसपास की दीवारों को विशेष रंग से पेंटिंग कराने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त ने मंदिर परिसर में जगह–जगह पान की पिच न थूकने संबंधी निर्देश लिखवाने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर निगम की टीम के साथ वह क्षीरेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर के सामने नाली पर सही ढंग से पत्थर लगवाने का निर्देश दिया, ताकि किसी भी श्रद्धालु को ठोकर न लगे। मंदिर परिसर में निरंतर सफाई के लिए कर्मचारियों को तैनात रखने को कहा।इसके साथ भंडारा स्थल तथा शिव–पार्वती विवाह की झांकी के दौरान भी सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था तथा सुगम दर्शन के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया।

मोदी–ट्रंप ट्रेड डील रद्द करने की मांग को लेकर आप का प्रदर्शन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, 14 फरवरी।आम आदमी पार्टी (आप) के जिलाध्यक्ष राम रतन विश्वकर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई कथित ट्रेड डील को तत्काल रद्द करने की मांग की। जिलाध्यक्ष राम रतन विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि यह समझौता देश के

किसानों और आम नागरिकों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि डील की शर्तों, संभावित लाभार्थियों और दूरगामी प्रभावों को लेकर देशभर में गंभीर चिंताएं हैं। पार्टी का आरोप है कि इस समझौते पर न तो संसद को विश्वास में लिया गया और न ही जनता के समक्ष पारदर्शिता बरती गई। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ भारतीय उद्योग समूहों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी कार्रवाई सामने आई है, ऐसे में इस डील की संवेदनशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पार्टी ने पूर्व में हुई राफेल डील का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी निर्णयों से चुनिंदा कॉरपोरेट समूहों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। आप नेताओं ने दावा किया कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत शुल्क लगाएगा, जबकि अमेरिकी उत्पादों पर शून्य शुल्क लागू होगा। उन्होंने आशंका जताई कि कृषि बाजार खुलने से सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी किसानों के मुकाबले भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। पार्टी ने सरकार से डील की शर्तें सार्वजनिक कर पुनर्विचार की मांग की है।

एसआईआर के सम्बन्ध में किया जनसंपर्क कर फार्म-7 के प्रति किया गया सतर्क

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। गोशाईंगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रभारीप्रदयाशी चौ.लौटनराम निषाद ने रामपुर पुवारी सेक्टर के दलपतपुर,आलापुर, रामपुर पुवारी मांझा,ईशासराय, दामोदरपुर, मांझा काजीपुर, काजीपुर रकौरा,रामपुर पुवारी उपरहार, नकटवारा, जरही आदि बूथों पर जनसंपर्क कर एसआईआर के सम्बन्ध में पार्टी समर्थकों व पदाधिकारियों से जानकारी लिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के पशोपेश में फंसी भाजपा–आरएसएस अब फार्म–7 के जरिए पीडीए विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं का वोट कटवाने के षड्यंत्र में जुटी हुई है।उन्होंने पार्टी समर्थकों,बीएलए व पदाधिकारियों से आग्रह किया कि बीएलओ के सम्पर्क में रहकर फार्म–7 के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है।फार्म–7 के दुरुपयोग की कहीं जानकारी मिले तो तत्काल हमें सूचना उपलब्ध करायें।06 जनवरी 2026 की ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाद प्रत्येक विधान सभा में लगभग सभी पोलिंग बूथों पर नाम काटे व नाम जोड़े गये हैं।ईआरओ ने प्रत्येक सप्ताह नाम काटने व नाम जोड़ने की सूची आपको दी है और नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित कर रहे हैं।काटे गये नाम,जोड़े गये नाम का घर–घर जाकर सत्यापन करवा लें। यदि किसी व्यक्ति का नाम गलत ढंग से कट गया है, या किसी गलत व्यक्ति का नाम जुड़ गया है। तत्काल लिखित शिकायत ईआरओ और जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी से करें। गोशाईंगंज प्रभारी चौ.लौटनराम निषाद ने कहा कि भाजपा द्वारा जमा किये जा रहे फार्म–7 पर सभी को सावधान रह कर एक–एक फार्म पर लिखित आपत्ति देना है और उसकी जानकारी प्रदेश कार्यालय को देना है। पार्टी समर्थक मतदाताओं विशेष कर 18–21 वर्ष के लोगों तथा जिनका नाम छूट गया है, सभी का फार्म–6 भरवाकर नाम दर्ज कराना है।नो–मैपिंग तथा लॉजिकल एरर वाले अपने मतदाताओं के दस्तावेज बनवाने में मदद करें तथा कार्यकर्ताओं को लगा कर सुनवाई अधिकारी तक पहुँचाना का कार्य करें।एसआईआर में शिकायत या समस्या प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष, निर्वाचन टीम को भेजने के लिए तत्पर रहना आवश्यक है। निषाद ने कहा कि भाजपा–आरएसएस लोकतंत्र व संविधान को कमजोर करने की साजिश में जुटा हुआ है।पकरैला सेक्टर के जोगापुर,राजापुर सरैया,जमुनीपुर, सुमेरपुर, पहाड़पुर, सरैया,बनघुसरा, सिकंदरपुर,पकरैला में जनसंपर्क कर एसआईआर व फार्म–6 व फार्म–7 के सम्बन्ध में चर्चा किया और फार्म–7 के माध्यम से भाजपा पीडीए व मुस्लिम मतदाताओं का नाम कटने की जो साजिश की जा रही है,बीएलए के सम्पर्क में रहकर अपनों का वोट बचाने के लिए सावधान रहना आवश्यक है।जनसंपर्क में समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव विजय बहादुर वर्मा,समाजवादी पिछड़ावर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव जगन्नाथ पाल,विकास पटेल,सिकंदर कन्नोजिया,जीतेन्द्र वर्मा,राकेश वर्मा,डा.रामू निषाद, झन्नूलाल प्रजापति,रामचेत विश्वकर्मा,आलोक वर्मा,रमापति यादव,मनोज वर्मा आदि शामिल रहे।

डॉक्टर को दिनदहाड़े गोली मारकर फरार हुए नकाबपोश बदमाश, रंगदारी की धमकी का आरोप

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, 14 फरवरी। यूपी के जौनपुर जिले के बक्शा थाना क्षेत्र स्थित लखौवा बाजार में शनिवार शाम करीब 3:30 बजे अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक डॉक्टर को गोली मार दी। घायल डॉक्टर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखौवा बाजार निवासी डॉ. वी.के. बंगाली अपने घर पर ही डिस्पेंसरी चलाते हैं। शनिवार को वह रोज की तरह मरीजों का उपचार कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे। तीनों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक से उतरे एक बदमाश ने अचानक पिस्तौल निकालकर डॉक्टर पर फायरिंग कर दी। बदमाश ने तीन राउंड फायर किए, जिनमें से एक गोली डॉक्टर के पैर में लगी, जबकि दो गोलियां मिस हो गईं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज से क्षेत्र में अफरा–तफरी मच गई और बाजार में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल डॉक्टर को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया। डॉ. बंगाली ने पुलिस को बताया कि 10 जनवरी को वह एक शादी समारोह में शामिल होने अपने घर गए थे और 6 फरवरी को लखौवा लौटे। इसी बीच उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक कॉल आई थी, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को 'सोले सिंह' बताते हुए 24 घंटे के भीतर 50 लाख रुपये की व्यवस्था करने की धमकी दी थी। रकम न देने पर गोली मारने की चेतावनी भी दी गई थी। थानाध्यक्ष लक्ष्मण विक्रम सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घटनास्थल की जांच की जा रही है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

दो सगे भाइयों ने पकड़े हाथ-पैर, आरोपी पति ने रेत दिया गला

गोरखपुर, (संवाददाता)। गीडा पुलिस ने नौसढ़ निवासी अभिषेक सिंह (18) की हत्या के मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी पति भागा हुआ है। उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध के शक में वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी पति नौसढ़ चौराहे पर फास्टफूड का ठेला चलाता है। आरोपी सगे भाई वहीं काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात वाले दिन सगे भाइयों ने अभिषेक के हाथ–पैर पकड़ लिए और आरोपी पति ने चाकू से गला रेतने के बाद कई वार करके उसे मार डाला। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहपुर के गीता वाटिका पानी की टंकी के पास आवास विकास कॉलोनी निवासी पवन कुमार और विजय के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। नौसढ़, पेवनपुर गांव के निवासी अभिषेक सिंह की बीते छह फरवरी की रात हत्या कर दी गई थी। सात फरवरी को खून से लतपथ उसका शव मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि धारदार हथियार से 35 जगह गंभीर वार किए गए थे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।